an>

Title: Need to take steps to check soil erosion caused by recurrent rains and floods in Jharkhand particularly in Palamu and Garhwa districts of the State.

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू) ः मिट्टी के कटाव से संबंधित प्रकाशित एक सर्वे की रिपोर्ट, जो भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केन्द्र (इसरो) की संस्था स्पेस एप्लीकेशन्स सेंटर, अहमदाबाद की अगुवाई में तैयार करवाई है, के तथ्य चौंकाने वाले और चिंताजनक हैं। सर्वे में दर्शाया गया है कि झारखण्ड में पिछले आठ साल में 80 हज़ार हैक्टयर भूमि मिट्टी के कटाव के कारण लगभग बंजर हो गई है। इस भूमि की उपजाऊ 15 सेंटीमीटर मिट्टी की परत बारिश और बाढ़ के कारण नालों और नदियों में बहती जा रही है। सर्वे के आधार पर तैयार रिपोर्ट में झारखण्ड प्रदेश के चार जिलों में स्थिति भयावह है, जिनमें मेरे संसदीय क्षेत्र अंतर्गत पलामू जिला भी है।

रिपोर्ट बताती है कि पलामू के कुल भू-भाग 8,02,291 हैक्टेयर में से 50,363 हैक्टेयर भूमि कटाव के दायरे में है, पलामू एवं गढ़वा जिलान्तर्गत उत्तर कोयल नदी, अमानत एवं सोन नदी से भीषण कटाव हो रहा है, जिससे न केवल कृषि योग्य भूमि कट रही है, बल्कि मकान भी कटने शुरू हो गए हैं, जिससे लोग घरबार छोड़कर दूसरी जगहों पर जा रहे हैं। खासकर उत्तर कोयल नदी के पूर्वी तट पर कादल गांव से सलखनी तक उटारी से मुहम्मदगंज तक, मुहम्मदगंज से मजनिया पंचायत में एवं श्रीनगर का इलाका पूरी तरह से कटाव की चपेट में आ गया है और नदी का पानी कम होने पर खेती योग्य भूमि में बालू एकत्र हो रहा है। यदि समय रहते इस भूमि कटाव पर शीघ्र नियंत्रण के लिए प्रभावकारी कदम नहीं उठाये गये तो लोगों को विवश होकर बड़ी संख्या में पलायन करना पड़ेगा।

मानव सभ्यता को बचाये रखने के लिए मिट्टी के क्षरण को रोकना बेहद जरूरी है। मिट्टी की एक उपजाऊ परत बनने में एक हज़ार साल लग जाते हैं।

मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि मिट्टी के कटाव जैसे संवेदनशील मुद्दे पर राज्य सरकार के साथ मिलकर जल्द ही कोई निर्णायक कदम उठाकर वर्तमान तथा संभावित समस्याओं को रोकने के लिए प्रयास शुरू करे।